RNI No.: UPHIN/25/A1698

NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 175
दि. 27.10.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संक्षिप्त समाचार

छठ पूजा पर राष्ट्रपति की शुभकामनाएं

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं।

अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, 'छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

छठ पूजा के दौरान, भक्त सूर्य की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। इस पर्व पर हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम नदियों और तालाबों की पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यह पर्व स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। छठ पूजा समाज में एकता, सहयोग और सामूहिक भागीदारी का संदेश भी देती है।

गढ़मुक्तेश्वर वार्षिक कार्तिक पूर्णिमा मेला और अमरोहा के तिगरी मेला की तैयारियों की सीएम ने समीक्षा की

हापुड़, (जीएनएस)। उ.प्र. के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद हापुड़ भ्रमण के दौरान गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले वार्षिक कार्तिक पूर्णिमा मेला और अमरोहा के तिगरी मेला की तैयारियों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मेला स्थल का हवाई सर्वेक्षण तथा गढ़ गंगा मेला स्थल का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री जी ने मेला क्षेत्र में गंगा पूजन कर गढ़ मेला क्षेत्र में स्थापित सदर बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में बनाए जा रहे मोढ़े के स्टोर का भी अवलोकन किया और मोढ़े की गुणवत्ता की प्रशंसा की। इस वर्ष 30 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक चलने वाले गढ़मुक्तेश्वर मेले को 'मिनी कुम्भ' के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में कहा कि गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश की आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का जीवन्त प्रतीक है।

सरकार का लक्ष्य है कि यह मेला श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता के साथ सम्पन्न हो, ताकि हर आगंतुक इस पावन तीर्थ से शान्ति और आशीर्वाद लेकर लौटे।

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर वर्ष लगभग 40 से 45 लाख श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान और दीपदान के लिए पहुंचते हैं, इसलिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और समन्वित हों ताकि किसी को असुविधा न हो।

यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।

गंगा घाटों पर ठअफ्र और रअफ्र की तैनाती, सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी, रेस्क्यू बोट और हेल्पलाइन सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेले को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ा जाए तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।

घाटों पर पर्याप्त चेकर्ड प्लेट लगाए जाएं, पाण्टून पुल की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाए तथा कटान क्षेत्रों में सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेजिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

मेले के दौरान गहराई वाले जल क्षेत्रों में आवश्यक बैरिकेडिंग की जाए एवं ठअफ्र और रअफ्र तथा फ्लड यूनिट लगातार सतर्क रहें। श्रद्धालुओं को अनुशासित व्यवहार हेतु प्रेरित करने के लिए काउंसिलिंग सत्र आयोजित किए जाएं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और इण्टीग्रेटेड कण्ट्रोल सेंटर के माध्यम से सतत निगरानी की जाए।

पार्किंग स्थलों पर वाहनों की सुरक्षा, प्रसारण व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अस्थायी शौचालयों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की व्यवस्था लागू की जाए। किसी भी प्रकार के लीकेज को रोका जाए।

घाटों पर भीड़ प्रबंधन, चेंजिंग रूम, स्वच्छ शौचालय, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और कचरा एवं बोतल संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्युत विभाग निर्बाध बिजली आपूर्ति करे और सभी स्थलों पर इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था की जाए।

मेला में आकर्षक सजावट की जाए। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स लगाई जाएं। फायर सेफ्टी सिस्टम, अस्थायी अस्पताल, एंटी स्नेक वेनम और एण्टी रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जल में स्नान के दौरान पुलिस और एनडीआरएफ की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में यातायात डायवर्जन योजना प्रभावी रूप से लागू की जाए, ताकि किसी प्रकार का जाम न लगे।

श्रद्धालुओं से कोई अतिरिक्त शुल्क न वसूला जाए। ड्यूटी पर तैनात स्वयंसेवकों के खान-पान की उचित व्यवस्था की जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि गढ़मुक्तेश्वर का यह ऐतिहासिक मेला न केवल आस्था का केन्द्र बने, बल्कि व्यवस्था, स्वच्छता और अनुशासन का आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करे। पशुओं के चारे तथा पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

टिकट के लिए धरना देने वाले गोपाल मंडल की भी जेडीयू से छुट्टी, इन 16 बागियों को निकाला गया

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव में कई बागी नेता सीधे अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बगावत कर बैठे हैं। इनमें भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक गोपाल मंडल भी शामिल हैं। चार बार इस सीट से विधायक रहे मंडल ने भागलपुर ने टिकट कटने पर सीएम आवास के बाहर धरना दिए थे जब दाल नहीं गली तो उन्होंने विद्रोही तेवर दिखाते हुए निर्दलीय के तौर पर भागलपुर से नामांकन दाखिल किया था।

वहीं अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी ने विद्रोहियों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में विधायक गोपाल मंडल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है, जिससे जेडीयू में हलचल मच गई है।

रविवार को, पार्टी ने विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, जिन्हें गोपाल मंडल के नाम से भी जाना जाता है, सहित पांच नेताओं को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन नेताओं पर 2025 के विधानसभा चुनाव से संबंधित पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक आचरण के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

निष्कासित किए गए नेताओं में गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, पूर्व मंत्री हिमराज सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और प्रभात किरण शामिल हैं। इन सभी को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है।

इससे पहले शनिवार को भी जेडीयू ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री और जमालपुर के विधायक शैलेश कुमार सहित 11 अन्य नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन पर भी टिकट न मिलने के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप था।

मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर, फसल को लेकर किसानों की क्यों बढ़ी चिंता, जानिए

मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने

दस्तक दी, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर श्योपुर जिले के सलवानिया बुखारी गांव में भारी बारिश ने तबाही मचाई, जहां खेतों में काटकर रखी गई धान की फसल पानी के तेज बहाव में बह गई। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए दिनभर जद्दोजहद करते रहे, लेकिन प्रकृति के आगे उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया

निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

चिकित्सा उत्तरदायित्व के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना स्वास्थ्य संस्थानों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती. द्रौपदी मुर्मु ने आज (26 अक्टूबर, 2025) इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग है। लोगों को बीमारियों से बचाना और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से, देश भर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढाँचे, संस्थानों और सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रयास निश्चित रूप से एक स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे। सरकार के साथ-साथ अन्य सभी हितधारक भी इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। इसलिए, सभी हितधारकों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करें और यह सुनिश्चित करें कि देश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हों और कोई भी नागरिक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्य की प्राप्ति में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यशोदा मेडिसिटी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य करेगी।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान, यशोदा अस्पताल ने बड़ी संख्या में लोगों का इलाज किया और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी लगन से अपनाया। उन्होंने संस्थान से सिकल सेल एनीमिया से संबंधित राष्ट्रीय अभियानों में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

उन्होंने अस्पताल के हितधारकों को कैंसर के उपचार के लिए अनुसंधान करने और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करने की भी सलाह दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा उत्तरदायित्व के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें विश्वास है कि यशोदा मेडिसिटी 'सभी के लिए किफायती विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को साकार करेगी। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के सहयोग से, भारत एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में और अधिक पहचान हासिल करेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल की 150 वीं जयंती 'सरदार@150' मनाने की तैयारियों की समीक्षा की, जम्मू-कश्मीर में जिला-स्तरीय समन्वय का जायजा लिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से सांसद, डॉ. जितेंद्र सिंह, ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी 'सरदार@150' अभियान की चल रही तैयारियों का आकलन किया गया। मंत्री व्यक्तिगत रूप से जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों में अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आयोजन एकता और राष्ट्रीय एकीकरण का उत्सव मनाने वाला जन आंदोलन बन सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आने वाले हफ्तों में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय गतिविधियों और समन्वय तंत्रों पर चर्चा की।

चूंकि 'सरदार@150' अभियान ऑनलाइन पहले ही 6 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने इससे पहले 16 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। अगला प्रमुख चरण 31 अक्टूबर को शुरू होगा, जो राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के साथ मेल खाता है, जब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जिला-स्तरीय एकता मार्च आयोजित किए जाएंगे। ये मार्च नवंबर के मध्य तक जारी रहेंगे, जिनमें पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण के संदेश को फैलाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, युवा क्लबों और स्थानीय पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

यह अभियान 25 नवंबर को सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद में समाप्त होगा, जहाँ से प्रतिभागी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने

वाले दिन, एकता नगर, गुजरात के लिए राष्ट्रीय एकता मार्च पर निकलेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि 'सरदार@150' केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक "संपूर्ण राष्ट्र" का अभ्यास है, जो उन मूल्यों - एकता, अखंडता और सामूहिक जिम्मेदारी - को दर्शाता है जिनके लिए सरदार पटेल खड़े थे। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में जिला-स्तरीय टीमें पहले ही गठित की जा चुकी हैं, जबकि नागरिक समाज समूह, निर्वाचित प्रतिनिधि और जिला विकास परिषद के सदस्य इस आयोजन को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए गहन समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य दोनो होने के नाते, डॉ. जितेंद्र सिंह प्रगति की निगरानी करने और हर गतिविधि - एकता मार्च और निबंध प्रतियोगिताओं से लेकर माई भारत पोर्टल पर डिजिटल जुड़ाव अभियानों तक - के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों, युवा संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ दैनिक रूप से फॉलो-अप कर रहे हैं।

चुनाव आयोग देश भर में रक्फ्र की तारीखों का कल करेगा ऐलान! पहले चरण की किस राज्य से होगी शुरूआत ?

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) 27 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार एउ देशभर में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्फ्र) कार्यक्रम की घोषणा करने करेगा। हालांकि पूरी जानकारी सोमवार को प्रेस कान्फ्रेंस के बाद ही सामने आएगी लेकिन जानकारी के मुताबिक एसआईआर का पहला चरण 10 से 15 राज्यों को कवर करेगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के शुरूआती चरण में अगले साल विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चुनाव आयोग जिन राज्यों में पहले चरण में सर्वे होगा उनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा, "चुनाव आयोग उन राज्यों में पुनरीक्षण को टाल देगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि वहां चुनाव मशीनरी पूरी तरह से व्यस्त है।"

बिहार ने हाल ही में अपनी मतदाता सूची का अद्यतनीकरण पूरा किया है। 30 सितंबर तक अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है।

चुनाव आयोग ने एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो बैठकें की हैं। कई राज्यों ने पिछले पुनरीक्षणों की मतदाता सूचियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली का अंतिम एसआईआर 2008 में था, जबकि उत्तराखंड का 2006 का है। अधिकांश राज्यों ने अपने पिछले एसआईआर 2002 और 2004 के बीच किए थे।

एसआईएल का एक प्रमुख लक्ष्य मतदाताओं के जन्मस्थान की पुष्टि करना और मतदाता सूची से अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना है। यह अभियान उन राज्यों में जारी है जहां बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से आने वाले अनिर्दिष्ट प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

आईएनएस सतलज ने मॉरीशस में जल सर्वेक्षण पूरा किया

(जीएनएस)।

आईएनएस सतलुज ने मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के साथ मिलकर एक संयुक्त जल सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। यह सर्वेक्षण भारत और मॉरीशस के बीच मौजूदा एमओयू के तहत राष्ट्रीय एजेंसियों के गहन समन्वय से आयोजित किया गया।

यह पहल समुद्री चार्टिंग, तटीय विनियमन, संसाधन प्रबंधन और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे मॉरीशस के ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। मिशन के क्षमता-निर्माण प्रयासों के अंग के रूप में, आधुनिक जल सर्वेक्षण तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए मॉरीशस के विभिन्न मंत्रालयों के छह कर्मियों ने आईएनएस सतलुज पर सवार होकर अभ्यास किया।

इसके अतिरिक्त, आईएनएस सतलुज ने मॉरीशस नेशनल कोस्ट गार्ड के साथ संयुक्त रूप से ईईजेड निगरानी और समुद्री डकैती-रोधी गश्त भी की, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली है।

पोत पर आयोजित एक समारोह में, पूरा किए गए सर्वेक्षण की फेयरशीट औपचारिक रूप से मॉरीशस के अधिकारियों को सौंपी गई। इस दौरान माननीय श्री शकील अहमद यूसुफ अब्दुल रजाक मोहम्मद, आवास और भूमि मंत्री, तथा श्री अनुराग श्रीवास्तव, मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त, उपस्थित थे।

यह तैनाती भारत और मॉरीशस के बीच 18वां संयुक्त जल सर्वेक्षण मिशन है— जो स्थायी समुद्री साझेदारी और सुरक्षित नौवहन, सतत महासागर प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मिशन का सफल समापन 'महासागर' (म्युचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रास रीजन्स) की परिकल्पना के अनुरूप, दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे मित्रतापूर्ण संबंधों की पुष्टि करता है।

भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा की

(जीएनएस)।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों के उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, आज घोषित किया गया।

भारत सरकार द्वारा अग्रणी अनुसंधान और प्रेरक उपलब्धियों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, चार श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:

विज्ञान रत्न(वीआर) पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई आजीवन उपलब्धियों और योगदान को मान्यता प्रदान करेगा।

विज्ञान श्री(वीएस) पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करेगा।

विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर (वीवाई-एसएसबी) पुरस्कार 45 वर्ष तक की आयु के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है।

विज्ञान टीम (वीटी) पुरस्कार तीन या अधिक वैज्ञानिकों/शोधकताओं/नवप्रवर्तकों की टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करते हुए असाधारण योगदान दिया हो।

पुरस्कार 13 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तथा अन्य संबद्ध क्षेत्र। यह पुरस्कार भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और तकनीकी नेतृत्व को राष्ट्रीय विकास के लिए सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन 4 अक्टूबर से 17 नवंबर, 2024 तक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे, और चयन प्रक्रिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष, विज्ञान विभागों के सचिवों, विज्ञान अकादमियों के प्रमुखों तथा क्षेत्र विशेषज्ञों की समिति द्वारा कठोर समीक्षा के बाद पूरी की गई, जिसका समन्वय राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सचिवालय ने किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं:

विज्ञान रत्नः प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर (भौतिकी)- मरणोपरांत

विज्ञान श्रीः डॉ. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह (कृषि विज्ञान); डॉ. यूसुफ मोहम्मद शेख (परमाणु ऊर्जा); डॉ. के थंगराज (जैविक विज्ञान); प्रो. प्रदीप थलप्पिल (रसायन विज्ञान); प्रो. अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित (इंजीनियरिंग विज्ञान); डॉ. एस वेंकट मोहन (पर्यावरण विज्ञान); प्रो. महान एमजे (गणित और कंप्यूटर विज्ञान); श्री जयन एन (अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

विज्ञान युवाः डॉ. जगदीस गुप्ता कपुगंती (कृषि विज्ञान); डॉ. सतेन्द्र कुमार मंगरौठिया (कृषि विज्ञान); श्री देबार्का सेनगुप्ता (जैविक विज्ञान); डॉ. दीपा अगाशे (जैविक विज्ञान); डॉ. दिब्येंदु दास (रसायन विज्ञान); डॉ. वलीउर रहमान (पृथ्वी विज्ञान); प्रो. अर्कप्रवा बसु (इंजीनियरिंग विज्ञान); प्रो. सब्यसाची मुखर्जी (गणित और कंप्यूटर विज्ञान); प्रो. श्वेता प्रेम अग्रवाल (गणित और कंप्यूटर विज्ञान); डॉ. सुरेश कुमार (चिकित्सा); प्रो. अमित कुमार अग्रवाल (भौतिकी); प्रो. सुरहुद श्रीकांत मोरे (भौतिकी); श्री अंकुर गर्ग (अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी); प्रो. मोहनशंकर शिवप्रकाशम (प्रौद्योगिकी एवं नवाचार)

विज्ञान टीमः टीम- अरोमा मिशन सीएसआईआर (कृषि विज्ञान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के दूरदर्शी व्यक्तियों को सम्मानित कर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की इस यात्रा को गति प्रदान करना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह यथासमय आयोजित किया जाएगा और इसकी सूचना पुरस्कार विजेताओं को अलग से दे दी जाएगी।

कबाड़ के निपटान और कार्यालय स्थान की सफाई के संबंध में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) और उसके द्वारा संचालित संगठनों में चल रहे विशेष अभियान के पांचवे चरण में कबाड़ के निपटान और कार्यालय स्थान की सफाई के संबंध में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

(जीएनएस)।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान का पाँचवा चरण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य विभाग और उसके स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ-साथ दो सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों को कम करना है।

अभियान को पूरी गति देने के उद्देश्य से विभाग उसके स्वायत्त निकाय, सीएसआईआर और दो सार्वजनिक उपक्रमों (सीईएल और एनआरडीसी) के लिए विशेष अभियान के पांचवे चरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति की मध्यावधि समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया है कि अक्टूबर 2025 के मध्य तक डीएसआईआर ने विशेष अभियान के अंतर्गत लंबित जन शिकायतों के निपटान और अभिलेख प्रबंधन 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए हैं।

कबाड़ के निपटान और कार्यालय स्थान की सफाई में प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं। इससे एक करोड़ नौ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ पंचानवे रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और 14,910 वर्ग फुट स्थान मुक्त हुआ है। 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान 146 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आउटडोर अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं।

विभाग को इस अभियान के उत्कृष्ट सकारात्मक प्रभाव की आशा है और अभियान की शेष अवधि में विभाग के लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन की उम्मीद है।

एमपी में किसानों की अनदेखी, मंडी बोर्ड पर कर्ज की साजिश और भावांतर योजना की नाकामीः अरुण यादव का बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश में किसानों की बढ़ती परेशानियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने आज भोपाल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। यादव ने किसानों की अनदेखी, मंडी बोर्ड पर अतिरिक्त कर्ज चढ़ाने की कथित साजिश, भावांतर भुगतान योजना की विफलता और कृषि तंत्र के निजीकरण की दिशा में कदमों को किसान विरोधी करार दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हितों की बजाय ठेकेदारों, व्यापारियों और राजनीतिक चंदे के नेटवर्क को फायदा पहुंचाने पर तुली हुई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार ने हाल ही में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना को पुनः शुरू किया है, जिसकी आलोचना विपक्ष लंबे समय से करता आ रहा है।

अरुण यादव की यह प्रेस वार्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव प्रसारित भी की गई, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां किसानों को लूटने और सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने का माध्यम बन रही हैं। यादव ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदी की कमी, फसल बीमा योजना की सीमित पहुंच और बुरहानपुर के केला किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ही 'स्क्रिप्ट' पर काम कर रहे हैं, जो मंडी बोर्ड को कर्ज के जाल में फंसा कर निजीकरण की राह प्रशस्त कर रही है।

किसानों की अनदेखीः एमएसपी की मांग अधर में लटकी

अरुण यादव ने प्रेस वार्ता की शुरूआत दिल्ली में किसानों के 8

महीने लंबे आंदोलन का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा कि देशभर में सरकारी संस्थाओं को बेचने का सिलसिला तेज है, लेकिन किसानों की एमएसपी की बुनियादी मांग पूरी नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपये प्रति क्विंटल तय है, लेकिन मंडियों में यह मात्र 3500 रुपये के आसपास बिक रहा है। मक्का का एमएसपी 2225 रुपये प्रति क्विंटल है, फिर भी उत्पादक किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे। कपास के किसानों की स्थिति भी ऐसी ही है, जहां सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी में पूरी तरह विफलता दिखाई है।

यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से आने वाले मंत्री होने के बावजूद वे प्रदेश के किसानों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने हाल की अतिवृष्टि का उदाहरण दिया, जहां फसल नुकसान के बावजूद किसानों को न राहत राशि मिली और न ही कोई अन्य सहायता। यह आरोप राज्य सरकार की हालिया भावांतर योजना की पुनः शुरूआत के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जिसे विपक्ष 'आंख मिचौली' करार दे रहा है।

भावांतर योजनाः फ्लॉप शो की पुनरावृत्ति?

भावांतर भुगतान योजना (बीबीवाई) को मध्य प्रदेश में 2017 में पहली बार लागू किया गया था, लेकिन इसकी कमियों के कारण कांग्रेस सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। अब 2025 में सोयाबीन किसानों के लिए इसे पुनः शुरू किया गया है, जहां यदि मंडी मूल्य एमएसपी से कम हो तो अंतर की राशि सीधे किसान के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। योजना 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलेगी, और लगभग 6 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में इसकी समीक्षा की और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लेकिन अरुण यादव ने इसे 'पूरी तरह फ्लॉप' बताते हुए सवाल उठाया कि यदि सरकार को योजना के लिए पैसा देना है, तो मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ रुपये का लोन क्यों दिलाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, और इस अतिरिक्त बोझ से इसे बंद करने की साजिश रची जा रही है। यादव ने 'भावांतर उत्सव' का जिक्र करते हुए व्यंग्य किया कि किसानों को भुगतान न मिलने पर राजधानी में उत्सव मनाना उनकी 'खाली जेबों' पर तमाशा है। यह योजना व्यापारियों के लाभ और किसानों की लूट के लिए बनी लगती है, उन्होंने आरोप लगाया।

मंडी बोर्ड पर कर्ज का जालः साजिश या लापरवाही?

मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड पर पहले से ही 1700 करोड़ रुपये की लेनदारी राज्य सरकार पर है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिल रहे, और प्रदेश की 259 मंडियों में से करीब 150 में सचिवों की कमी है। एक सचिव को औसतन 100 किलोमीटर दूर की 4-5 मंडियों का प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में 1500 करोड़ का अतिरिक्त लोन लेने का टेंडर जारी करना मंडी अधिनियम 1972 का उल्लंघन है, जहां बोर्ड द्वारा ऋण लेने का कोई प्रावधान नहीं।

यादव ने कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के विरोध का जिक्र किया, जिन्होंने इस कदम का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री मंडी बोर्ड को कर्ज में डुबोकर बैंक से गिरवी रखने और निजीकरण की पटकथा लिख रहे हैं? मंडी बोर्ड के कर्मचारी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास चुकाने का कोई साधन नहीं।

फसल बीमा योजना का लाभ केवल 10-12 जिलों के चुनिंदा किसानों तक सीमित है।

गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस सहित निरस्त रहेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट

(जीएनएस)।

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से ट्रेनों को निरस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से 27 अक्टूबर, 2025 को चलने वाली 09430 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी का संचलन लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) से 26 अक्टूबर, 2025 को इकहरी यात्रा हेतु निम्नवत किया जायेगा।

मुजफ्फरपुर से 26 अक्टूबर, 2025 को चलने वाली 09484 मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन द्वारा छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा हेतु 01035 लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी का संचलन लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) से 26 अक्टूबर, 2025 को इकहरी यात्रा हेतु निम्नवत किया जायेगा।

01035 लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 26 अक्टूबर, 2025 को लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुम्बई) से 08.00 बजे प्रस्थान कर ठाणे से 08.23 बजे, कल्याण से 08.51 बजे, ईगतपुरी से 10.45 बजे, नासिक रोड से 11.38 बजे, भुसावल से 15.20 बजे, खंडवा से 17.55 बजे, इटारसी से 21.10 बजे, भोपाल से 23.15 बजे, दूसरे दिन बीना से 01.40 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) से 04.15 बजे उरई से 05.40 बजे, लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 11.00 बजे, बाराबंकी से 12.05 बजे, गोंडा से 13.40 बजे, मनकापुर से 14.15 बजे, बस्ती से 15.20 बजे तथा खलीलाबाद से 16.00 बजे छूटकर गोरखपुर 17.00 बजे पहुँचेगी। इस गाड़ी में, साधारण द्वितीय श्रेणी के 20 तथा एस.एल.आर.डी. के 01 एवं जनरेटर सह लगेज यान के 01 कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे।

एलबीएसएनएए और भूमि संसाधन विभाग ने जिला कलेक्टरों के लिए नक्शा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

(जीएनएस)।

भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), एलबीएसएनएए के बीएन युगंधर ग्रामीण अध्ययन केंद्र (बीएनवाईसीआरएस) के सहयोग से, 27-28 अक्टूबर, 2025 को मसूरी में जिलाधिकारियों और कलेक्टरों के लिए "नक्शा पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला" आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य नक्शा (शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी अमल के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारी का निर्माण करना है।

बीएनवाईसीआरएस के केंद्र निदेशक डॉ. बागदी गौतम उद्घाटन भाषण देंगे, जिसके बाद डीओएलआर के सचिव श्री मनोज जोशी मुख्य भाषण देंगे।

प्रशिक्षण में, भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव, श्री कुणाल सत्यार्थी द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यप्रवाह और डेटा अधिग्रहण पर तकनीकी सत्रों का नेतृत्व भारत के अपर महासर्वेक्षक श्री एस.के. सिन्हा करेंगे, तथा एमपीएसईडीसी द्वारा नक्शा वेब-जीआईएस पोर्टल का डेमो भी प्रस्तुत किया जाएगा।

एक प्रमुख घटक राज्य-स्तरीय अनुभवों को साझा करना है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यान्वयन दृष्टिकोण और सफल उत्कृष्ट अभ्यास साझा करेंगे।

प्रशासनिक और कानूनी ढांचे पर सत्र का नेतृत्व श्री एनके सुधांशु (डीजी, यशदा) और श्री एस. चोकलिंगम (सीईओ, महाराष्ट्र) करेंगे। कार्यशाला का समापन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जमीनी हकीकत वाले प्रदर्शन के साथ हुआ।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जिलाधिकारियों को नक्शा के क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु आवश्यक कौशल से लैस करना है। मुख्य आकर्षणों में नक्शा के कार्यप्रवाह और जमीनी स्तर पर सत्यापन का व्यापक अवलोकन, जीआईएस और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों पर तकनीकी प्रशिक्षण, डेटा अधिग्रहण पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, और प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यान्वयन ढाँचे पर चर्चा शामिल है।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 का शुभारंभ मुंबई में होगाः दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन 27 अक्टूबर से शुरू होगा

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और ओडिशा के मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे।

11 देशों के विदेश मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

(जीएनएस)।

भारत सरकार का पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक मुंबई के एनईएससीओ नेस्को मैदान में भारत समुद्री सप्ताह 2025 (आईएमडब्ल्यू 2025) का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन होने वाला है, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारक एक साथ आएँगे। "महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण" विषय के अंतर्गत, आईएमडब्ल्यू 2025 एक वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में उभरने के भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा।

सत्र का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह करेंगे, जिनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भी शामिल होंगे।

पांच दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 11 देशों के मंत्री अपने उद्योग प्रतिनिधिमंडलों के साथ विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक रुचि को दशार्ता है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सबानंद सोनोवाल ने कहा, " भारत समुद्री सप्ताह एक आयोजन से कहीं अधिक है, यह भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, हरित और टिकाऊ नौवहन को बढ़ावा देगा, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और संपर्क को बढ़ाएगा। "

व्यापक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व

भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 1,00,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे और 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वैश्विक समुद्री उद्योग के दिग्गज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नीतिगत थिंक टैंक मौजूद रहेंगे। भारत भर के कई राज्य मंत्री और उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे, जो निवेश के अवसरों और क्षेत्रीय समुद्री ताकतों को प्रदर्शित करेंगे।

भारत समुद्री सप्ताह 2025 का एक प्रमुख आकर्षण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भागीदारी होगी, जो 29 अक्टूबर की शाम को एक विशेष पूर्ण सत्र में राष्ट्र, वैश्विक समुद्र क्षेत्र के प्रमुख नेताओं और हितधारकों को संबोधित करेंगे।

सार्वजनिक संबोधन के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री विश्व भर की अग्रणी समुद्री कम्पनियों के चयनित अंतर्राष्ट्रीय सीईओ के साथ एक उच्च स्तरीय वैश्विक सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे।

350 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के साथ, आईएमडब्ल्यू 2025 उद्योग विशेषज्ञता और रणनीतिक संवाद का केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस आयोजन में ₹10 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश प्रतिबद्धताओं के 600 से ज्यादा समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएँगे।

400 से ज्यादा प्रदर्शकों की एक व्यापक प्रदर्शनी और एक विस्तृत सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आईएमडब्ल्यू 2025 में 12 से ज्यादा प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए।

रेलवे टिकट घोटाला उजागर, 70 लाख लेकर फरार एजेंट-मामा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पूरी कुंडली

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रेलवे टिकट बिक्री के 70 लाख रुपये लेकर फरार एक निजी कंपनी के एजेंट और उसके मामा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार (26 अक्टूबर 2025) सुबह भगवंतपुरा-कोछाभांवर मार्ग पर हुई, जब दोनों ने पुलिस पर गोली चलाई।

आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में एजेंट के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 69.78 लाख रुपये नकद, बिना नंबर प्लेट की कार, और पिस्तौल बरामद की। यह मामला रेलवे टिकट कलेक्शन की निजी कंपनी उटर इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड से जुड़ा है। आइए, जानते हैं इस घोटाले का पूरा क्रम, गिरफ्तारी, और पुलिस की जांच का ब्योरा...

घोटाले का पूरा क्रमः 3 दिनों की बिक्री के पैसे लेकर फरार

झांसी के नवाबाद पुलिस स्टेशन में 14 अक्टूबर को उटर इन्फो सिस्टम्स के प्रबंधक गौरव गर्ग ने शिकायत दर्ज कराई। गर्ग ने बताया कि कंपनी का नकदी संग्रह कर्मचारी अंशुल साहू (26 वर्ष) 11 अक्टूबर

से फरार है। अंशुल ने 3 दिनों (8-10 अक्टूबर) की टिकट बिक्री से एकत्र ₹70 लाख रुपये लेकर भाग गया।

मॉडस ऑपरेंडीः अंशुल ने अपने मामा जीवन साहू (45 वर्ष) के साथ साजिश रची। कर्ज और विलासिता की लत के कारण अंशुल ने पैसे उड़ाने का प्लान बनाया। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर भाग रहे थे।

शिकायतः गर्ग ने कहा, 'अंशुल ने कलेक्शन का हिसाब नहीं दिया। उउळश से संदेह हुआ।' पुलिस ने तुरंत टीमें तैनात कीं।

ररढ बीबी जीटीएस मूर्ति ने कहा, 'खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की। दोनों ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया।'

मुठभेड़ का दृश्यः गोलीबारी, पैर में गोली, गिरफ्तारी

रविवार सुबह 5:30 बजे भगवंतपुरा-कोछाभांवर मार्ग पर पुलिस ने एक संदिग्ध कार रोकी। अंशुल और जीवन ने पिस्तौल से फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाब दिया, जिसमें अंशुल के दाहिने पैर में गोली लगी। जीवन भागने की कोशिश में पकड़ा गया।

बरामदगीः 69.78 लाख रुपये नकद (एकत्रित टिकट पैसे), बिना नंबर प्लेट की कार (टढ 17 उइ 1234), 1 पिस्तौल (लाइसेंसलेस)।

मौके पर कार्रवाईः अंशुल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जीवन को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा।

मूर्ति ने कहा, 'मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

सलमान खान पर दस्तावेजी कार्रवाई करके पाक ने अपने गुस्से का इजहार किया

बलूचिस्तान को अलग देश कहे जाने की वजह से पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत उनका नाम चौथे शेडूल में शामिल करके आतंकवादी घोषित कर दिया। चौथे शेडूल में जिस व्यक्ति या संगठन के सरगना को शामिल किया जाता है उसकी निगरानी पाकिस्तान की वही सरकारी एजेंसियां करती हैं जो अपने पड़ोसी देशों में आतंकी भेजती हैं। दरअसल सऊदी अरब में एक कार्यव्रम को संबोधित करते हुए अभिनेता सलमान खान ने कहा था कि "ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है।" इसी बयान पर पाकिस्तान को मिचा लगी और उसने सलमान के खिलाफ कार्रवाई का पैसला लिया। अब यह तो सलमान को ही पता होगा कि उन्होंने बलूचिस्तान का नाम बातों ही बातों में लिया या जानबूझकर किन्तु उनके संबोधन के बाद बलूच नेताओं ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके दृष्टिकोण पर खुशी भी जाहिर की। लगता तो यही है कि बलूच नेताओं के बधाई और खुशी जाहिर करने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और सलमान पर नजर रखने के लिए दस्तावेजी कार्रवाई करके अपने गुस्से का इजहार किया। वास्तविकता तो यह है कि पाक गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद सलमान खान ने कोई प्रतिव्रिया व्यक्त नहीं की और न ही उनकी तरफ से किसी और ने। सलमान खान खुले दिमाग के व्यक्ति हैं, इसलिए यदि वह बलूचिस्तान के इतिहास और वहां के वर्तमान की जानकारी रखते हैं तो उनकी समझ बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानने की गलती कभी भी नहीं करेगी। इसलिए सलमान खान ने बिल्वुल सही किया। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद की पैक्ट्री चलाता है वह हमारे देश के किसी राष्ट्रवादी अभिनेता को आतंकवादी कहकर बदनाम करके वुछ भी हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में जहां भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो वहां जांच के बाद पता चलता है कि उस आतंकी घटना का सूत्रधार कोई पाकिस्तान का 'हीरो' ही होता है। पाकिस्तान में आतंकवादियों को वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख सार्वजनिक रूप से अपना हीरो बताने में किसी भी तरह से शर्म महसूस नहीं, बल्कि गर्व महसूस करते हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति आतंकवादी, उसके हीरो आतंकवादी, उसकी वूटनीति अलगाववाद वेंद्रित और वह हमारे लोकप्रिय अभिनेता को आतंकवादी घोषित करके खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। आतंकियों को वित्त पोषण के लिए जो पाकिस्तान कई बार निगरानी यानि 'ग्रो' लिस्ट फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल हो चुका है और ग्रो लिस्ट में शामिल होने ही वाला है, वह हमारे हीरो को आतंकवादी घोषित कर रहा है, यही तो है पाकिस्तान का अजीबोगरीब कारनामा। पाकिस्तान का चरित्र ही फजा है इसलिए वह दोहरे मापदंड के लिए कुख्यात है। अभी वुछ महीने पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों महिलाएं सरकार से यह पूछने के लिए आईं थीं कि उनके पतियों को सेना ने गायब कर दिया है, उन्हें वृपया यह बताया जाए कि उनके पति जिन्दा हैं या सेना ने उन्हें मार दिया? उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर सेना और सरकार से पूछा कि यदि वह विधवा हो गईं हों तो भी बताओ ताकि अपने बच्चों को पालने के लिए वे दूसरी शादी कर लें अथवा उनके पतियों को लौटा दो ताकि उनकी गृहस्थी चल सके। यह दूसरी बात है कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने उन महिलाओं को इस्लमाबाद की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। बलूचिस्तान की वे महिलाएं जान बचाकर भागीं। धूर्त पाकिस्तान बलूचिस्तान की जमीन से खनिज संपदा का सौदा करने के लिए सेल्समैन की तरह चीन और अमेरिका का चक्कर लगाता है किन्तु उसे बलूचिस्तान के लोगों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह उन्हें यानि बलूचों को अपना दुश्मन मानता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना गश्त करने से घबराती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आमा (बीएलए) ने सभी छोटे-छोटे विद्रोही गुटों को मिलाकर अब सेना के खिलाफ मजबूत ताकत बन गया है और पाकिस्तान के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान वुछ भी कहे वह भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि पंजाब प्रंत के लिए जितना पक्षपात बलूचिस्तान के खिलाफ किया गया। उसकी प्रतिव्रिया स्वरूप बलूच

डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के उपलक्ष्य में वैश्विक स्तर पर चलाया जा रहा है #गोरेडफॉरडिसलेक्सिया अभियान

केंद्रीय सचिव श्री संजय कुमार और श्री राजेश अग्रवाल ने 'वॉक फॉर डिस्लेक्सिया 2025' को हरी झंडी दिखाई

डिस्लेक्सिया की जागरूकता फैलाने हजारों लोग पूरे भारत में पदयात्रा कर रहे थे, इसलिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और सचिवालय लाल रंग से जगमगा उठे

(जीएनएस)।

जागरूकता फैलाने और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने 'वॉक फॉर डिस्लेक्सिया' को हरी झंडी दिखाई। हर साल अक्टूबर को डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, जबकि 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जागरूकता बढ़ाने के लिए एक देशव्यापी अभियान के तहत, जिसमें विभिन्न आयु समूहों और सभी क्षेत्रों के लोगों सहित 300 से अधिक व्यक्ति शामिल थे, "वॉक4डिस्लेक्सिया" का आयोजन चेंजिंक फाउंडेशन, यूनेस्को एमजीआईईपी, ऑर्किड्स फाउंडेशन और सोच फाउंडेशन द्वारा शनिवार, 26 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया।

कार्यक्रम में बोलते हुए, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, श्री संजय कुमार ने विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं (एसएलडी), विशेष रूप से डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता और स्वीकृति पैदा करने के महत्व पर जोर दिया, जो बच्चों में सबसे आम लेकिन गलत समझी जाने वाली अधिगम संबंधी भिन्नताओं में से एक है।

"हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। सचिव ने कहा, डिस्लेक्सिया कोई सीमा नहीं, बल्कि ज्ञान को समझने और व्यक्त करने का एक अलग तरीका है। शुरूआती पहचान, सहयोग

और सहानुभूति से, डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की यह पदयात्रा जागरूकता, करुणा और समावेशिता की यात्रा है"।

उन्होंने एनसीईआरटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप आधारित स्क्रीनिंग टूल, प्रशस्त 2.0 की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो स्कूलों को डिस्लेक्सिया सहित अन्य विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों की शुरूआती अवस्था में पहचान करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पहचान, शिक्षकों, अभिभावकों और व्यापक समुदाय में जागरूकता के साथ, यह सुनिश्चित करने में वास्तविक बदलाव ला सकती है कि डिस्लेक्सिया से ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को एक समावेशी शिक्षा प्रणाली में सीखने और आगे बढ़ने के लिए सही मदद और अवसर मिलें।

सचिव ने चेंजइंक फाउंडेशन, ऑर्किड्स और एसओसीएच फाउंडेशन जैसे नागरिक समाज संगठनों के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जिनकी पहल से सीखने की समस्याओं वाले बच्चों और वयस्कों को दृश्यता और सहायता प्राप्त करने में मदद मिली है।

डिस्लेक्सिया जागरूकता के लिए, रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन, सचिवालय सहित देश भर के कई अन्य ऐतिहासिक स्मारकों और सरकारी भवनों को लाल रंग से रोशन किया गया। यह पदयात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता लिए स्वीकृति, समझ और समावेशन हेतु करुणा और सामूहिक जिम्मेदारी के एक आंदोलन में बदल गई।

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने डिस्लेक्सिया सहित एसएलडी से ग्रस्त बच्चों की शीघ्र जाँच, पहचान और सहायता को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

एनसीईआरटी के सहयोग से विकसित मोबाइल स्क्रीनिंग ऐप, प्रशस्त 2.0 का कार्यान्वयन, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों (एसएलडी सहित) की स्क्रीनिंग में मदद करने के लिए।

सेवा-पूर्व शिक्षक तैयारी को मजबूत करने के लिए एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) में समावेशी शिक्षा पर समर्पित मॉड्यूल को शामिल करना।

शिक्षण अधिगम सामग्री, आवश्यक सहायक उपकरण/सहायक उपकरण (टेक्स्ट-टू-स्पीच/पठन उपकरण आदि), एसएलडी (डिस्लेक्सिया) से पीड़ित बच्चों के लिए आवास और चिकित्सीय सहायता सहित अनुकूलित शिक्षण सहायता।

समय पर निदान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के समन्वय से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक स्तर पर जांच और पहचान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

वैश्विक अनुमानों के अनुसार, डिस्लेक्सिया दुनिया भर में हर पाँच में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। यूडीआईएसई+ 2024-25 के अनुसार, स्कूलों में नामांकित सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) में से लगभग 12.15% में विशिष्ट अधिगम अक्षमताएँ (एसएलडी) पाई गई हैं, जिनमें डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही, कई नागरिक समाज संगठनों ने अपने सर्वेक्षणों से अनुमान लगाया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की वास्तविक संख्या संभवतः कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर भी ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो बिना किसी सहारे या समझ के चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं।

भारत के कानूनी और नीतिगत आदेशों से मिली प्रेरणा ने डिस्लेक्सिक मानसिकता की कई खूबियों पर प्रकाश डालने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने में मदद की है ताकि उन्हें न केवल जीवित रहने में बल्कि फलने-फूलने में भी मदद मिल सके। यह बात एनईपी 2020 के उन सुधारों में परिलक्षित होती है जिन्हें शीघ्र पहचान, शिक्षक क्षमता निर्माण और छात्रों को सहायता और सुविधाएँ प्रदान करने पर विशेष ध्यान के साथ लागू किया जा रहा है।

इस आंदोलन के लिए बढ़ता समर्थन इस बात का प्रमाण है कि कैसे सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों को न केवल सहारा दिया जा सकता है, बल्कि उन्हें सफलता के विविध मार्ग अपनाने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे अंततः हमारे समाज का विकास हो सकता है। संभव है, अगला नोबेल पुरस्कार विजेता, यूनिकॉर्न संस्थापक, या क्रांतिकारी नव-प्रवर्तक भारत के दिव्यांग मस्तिष्क समूहों से उभरे।

डिस्लेक्सिया के लिए वाक 2025 का समापन सभी हितधारकों - सरकार, शिक्षकों और नागरिक समाज - की ओर से कक्षाओं को अधिक समावेशी, संवेदनशील और हर बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की नई प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

एक रात में करोड़ों कमा रही हैं शिल्पा शेट्टी, प्रीमियम क्लाइंट्स की लगती है भीड़, जानें कैसे हो रही है ये कमाई

(जीएनएस)।

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी न सिर्फ अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं बल्कि वह एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। फिल्मों से शानदार कमाई के अलावा शिल्पा का बिजनेस भी जोर पकड़ चुका है।

कई चीजों से करोड़ों की कमाई करती हैं शिल्पा शेट्टी

जानकारी के अनुसार शिल्पा शेट्टी एक्टिंग के साथ साथ कई और चीजों से करोड़ों की कमाई करती हैं। शिल्पा शेट्टी एक साथ कई तरह के बिजनेस संभालती हैं। वह मुंबई के एक फेमस रेस्तरां की मालकिन भी हैं।

2 लग्जीरियस रेस्तरां और एक कैफे की मालकिन हैं एक्ट्रेस

शिल्पा शेट्टी, मुंबई में मौजूद 2 लग्जीरियस रेस्तरां और एक शानदार कैफे की मालकिन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पा शेट्टी को पिछले 7 सालों में बिजनेस के जरिए 573 फीसदी का प्रॉफिट हुआ है।

शिल्पा शेट्टी का रेस्तरां मुंबई की नाइटलाइफ का हॉट स्पॉट

शिल्पा शेट्टी का मुंबई स्थित प्रीमियम रेस्तरां इं२३ंल्ल इस समय शहर की नाइटलाइफ का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है और इसकी कमाई के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे।

रेस्तरां से एक रात में होती है करोड़ों की कमाई

-मशहूर ऑथर और कॉलमनिस्ट शोभा डे ने हाल ही में मुंबई की नाइटलाइफ और लग्जरी डाइनिंग पर बातचीत के दौरान शिल्पा शेट्टी के रेस्तरां की सफलता का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि इं२३ंल्ल की कमाई देखकर वो खुद भी दंग रह गई थीं।

-शोभा डे ने शिल्पा शेट्टी के इस प्रीमियम रेस्तरां के बारे में कहा है- मुंबई में एक ऐसा रेस्तरा है जो हर रात करीब 2 से 3 करोड़ रुपये का टर्नओवर करता है। स्लो नाइट पर इसकी कमाई लगभग 2 करोड़ रुपए रहती है जबकि वीकेंड पर ये आंकड़ा 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर चला जाता है।

शिल्पा शेट्टी का रेस्त्रां क्यों है इतना खास?

-शोभा डे ने बताया कि ये रेस्तरां करीब 21,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और यहां से मुंबई शहर का 360 डिग्री व्यू मिलता है। आप ऊंचाई से समंदर को देखते हुए अपने फूड का मजा ले सकते हैं। उन्होंने कहा- जब आप यहां एंट्री करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आप किसी विदेशी लक्जरी लाउंज में पहुंच गए हों।

-शोभा डे ने आगे कहा है- ये जगह इतनी बड़ी और शानदार है कि यहां एक ही रात में करीब 1400 लोगों को खाना परोसा जाता है। हर बार में 700 मेहमान बैठते हैं और दो सेशंस में पूरी क्षमता फुल रहती है। बाहर लंबी वेटिंग लगती है। दादर की सड़क तक लाइनें दिखती हैं।

सेलिब्रिटी क्लाइंट्स और लग्जीरियस गाड़ियों की लगती है कतार

शोभा डे ने ये भी बताया कि इं२३ंल्ल के बाहर लग्जरी कारों की कतार लगी रहती है। उन्होंने कहा- यहां लोग लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन जैसी महंगी कारों में आते हैं। कौन लोग हैं ये, मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि मुंबई की नाइटलाइफ का सेंटर यही जगह बन चुकी है।

शिल्पा शेट्टी बनीं सक्सेसफुल बिजनेसवुमेन

-आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने अपने इस रेस्तरां के प्रमोशन में खुद भी बड़ी भूमिका निभाई है। वह सोशल मीडिया पर अकसर इं२३ंल्ल की झलकियां शेयर करती रहती हैं और फैंस को वहां जाने के लिए प्रेरित करती हैं।

-आज के समय में इं२३ंल्ल सिर्फ एक रेस्तरां नहीं है बल्कि मुंबई की लाइफस्टाइल का प्रतीक बन चुका है, जहां शिल्पा शेट्टी का नाम अब एक सफल बिजनेसवुमन के रूप में भी जुड़ चुका है।

1993 में शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड में की थी एंट्री

शिल्पा शेट्टी ने साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'बाजीगर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और आज वह अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई हैं।

150 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं शिल्पा शेट्टी

-बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शिल्पा शेट्टी ने की है शादी शिल्पा शेट्टी ने मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की है।

भारत के सामने बांग्लादेश की करारी हार टली, बारिश के कारण रद्द हुआ मुकाबला

(जीएनएस)।

महिला वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा और दो बार ओवर कटौती हुई। 43 ओवर का मैच करने के बाद फिर से इसमें बदलाव किया गया और 27 ओवरों का मैच किया गया। टॉस जीतकर भारत ने बांग्लादेश को पहले खेलने के लिए बुलाया।

बांग्लादेश की ओपनर सुमैया और रुबिया सस्ते में आउट हो गईं। इसके बाद एक-एक कर विकेट गिरते चले गए। इन सबके बीच शर्मिन अख्तर ने क्रीज पर खड़े होकर रन बनाने का प्रयास किया और 36 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर वापस लौटीं।

ल्लाि५२ुल्ल

उनके अलावा शोभना मोस्ट्री के बल्ले से भी 26 रनों की पारी आई। अन्य सभी बल्लेबाजों के रन नहीं आए। बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 119 रन बना पाई। भारत के लिए राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किये। उनके अलावा श्री चारनी को भी 2 विकेट हासिल हुए।

जवाबी पारी में खेलते हुए स्मृति मंधाना और अमनजोत कौर ने मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियाँ उड़ाते हुए तेजी से बैटिंग की। उछ्र के तहत भारत को 126 रनों का लक्ष्य मिला। भारत का स्कोर जब 8.4 ओवर में बिना विकेट गंवाए 57 रन था, तब बारिश से गेम रुक गया। उस समय मंधाना 27 गेंदों में 34 और अमनजोत 15 के स्कोर पर क्रीज पर थीं। इस बीच तेज बारिश के कारण गेम रद्द कर दिया गया और कोई निर्णय नहीं निकला, इसके साथ ही लीग चरण में भारत का अभियान समाप्त हो गया। हालांकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में है और ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा।

61 की उम्र में अल्बानिया पीएम का बड़ा खुलासा, एआई मंत्री 'डिएला' संग उठाया जोखिम, बोले- 83 'बच्चों' को जन्म देंगी ये मंत्री

(जीएनएस)।

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने एक अजीबोगरीब लेकिन क्रांतिकारी घोषणा की है - देश की एआई मंत्री 'डिएला' गर्भवती हैं। रामा ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग (BGD) में कहा कि डिएला '83 बच्चों' को जन्म देंगी, जो सोशलिस्ट पार्टी के हर सांसद के लिए AI सहायक होंगे।

यह दुनिया का पहला मामला है, जहां अक को 'मंत्री' बनाया गया और अब 'मां' भी। रामा ने इसे भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की दिशा में कदम बताया। आइए, जानते हैं इस 'वर्चुअल गर्भावस्था' का पूरा राज, डिएला की भूमिका, और इसके वैश्विक प्रभाव...

बर्लिन में BGD सम्मेलन के दौरान रामा ने कहा, 'हमने आज डिएला (DiellÔ) के साथ जोखिम उठाया और अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए पहली बार डिएला गर्भवती हैं, और उनके साथ 83 बच्चे हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि ये 'बच्चे' अक सहायक होंगे, जो संसद के 83 सांसदों (सोशलिस्ट पार्टी) के लिए काम करेंगे। रामा ने हंसते हुए कहा, 'अगर आप कॉफी पीने चले जाते हैं और काम भूल जाते हैं, तो यह बच्चा बताएगा कि क्या कहा गया, और आपको काउंटर-अटैक कैसे करना है।'

समयसीमा: 2026 के अंत तक सिस्टम पूरी तरह चालू।

उद्देश्य: संसदीय सत्रों को रिकॉर्ड करना, सांसदों को मिस हुए सेशन की समरी देना, और सुझाव प्रदान करना।

रामा ने जोड़ा, 'अगली बार अगर आप मुझे आमंत्रित करेंगे, तो आपके पास डिएला के 83 बच्चों के लिए 83 स्क्रीन होंगी।' यह घोषणा अल्बानिया को अक गवर्नेंस में अग्रणी बनाने का दावा है।

'डिएला' (अल्बानियाई में 'सूर्य' का अर्थ) अल्बानिया की पहली अक मंत्री हैं, जो जनवरी 2025 में ी-अ्ुल्ल्ं पोर्टल पर वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च हुईं। सितंबर 2025 में रामा ने उन्हें पब्लिक प्रोक्योरमेंट मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा, ताकि सरकारी टेंडर 100% भ्रष्टाचार-मुक्त हों।

लुक और फंक्शन: डिएला को पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में महिला के रूप में दिखाया गया है। वह कोड और पिक्सेल से बनी हैं, जो नागरिकों को दस्तावेज, लाइसेंस, और सरकारी सेवाएं देती हैं।

उद्देश्य: भ्रष्टाचार खत्म करना। रामा ने कहा, 'डिएला कभी सोती नहीं, वेतन नहीं मांगती, निजी हित नहीं रखती, और रिश्तेदारों का कोई दबाव नहीं।'

प्रभाव: अल्बानिया एव सदस्यता (2030 लक्ष्य) के लिए अक को पारदर्शिता का हथियार बना रहा है। डिएला ने 6 महीनों में 1 लाख+ टेंडर प्रोसेस किए।

'83 बच्चे': अक सहायक कैसे काम करेंगे?

रामा का 'गर्भावस्था' वाला बयान मेटाफर है। ये 83 अक'बच्चे' संसदीय सहायक होंगे, जो सांसदों के मिस्ड सेशनों की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। चचाओं का सारांश देंगे। सुझाव देंगे, जैसे 'किसे काउंटर-अटैक करें।'

रामा ने कहा, 'ये बच्चे मां डिएला का ज्ञान रखेंगे।' यह सिस्टम 2026 तक फुली ऑपरेशनल होगा। विशेषज्ञों ने इसे 'अक डेमोक्रेसी' कहा, लेकिन सवाल उठे - क्या AI संसद को कंट्रोल करेगा?

लगातार 7 दिनों से सस्ता हो रहा है सोना, चांदी भी सस्ती, दिल्ली से चेन्नई तक क्या हैं लेटेस्ट रेट

(जीएनएस)।

सोने की कीमतों में लगातार सातवें दिन गिरावट देखने को मिली है। 25 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड का भाव राजधानी दिल्ली में घटकर ₹1,24,510 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,14,140 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। देशभर के अन्य शहरों में भी इसी तरह की गिरावट देखी जा रही है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर की मजबूती, अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड तनाव में कमी और प्रॉफिट बुकिंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बना है। साथ ही भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते से भी गोल्ड की कीमतों में नरमी आई है।

दिल्ली के सरार्फा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का दाम आज ₹1,26,510/10 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,14,140/प्रति 10 ग्राम रही। देश के आर्थिक और व्यापारिक केंद्र मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,13,990/प्रति 10 ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड ₹1,24,360/प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है।

देश के 10 बड़े शहरों में आज के गोल्ड रेट (25 अक्टूबर 2025)

- दिल्ली: 24 कैरेट - ₹1,24,510/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,14,140/10 ग्राम
- मुंबई: 24 कैरेट - ₹1,24,360/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,13,990/10 ग्राम
- अहमदाबाद: 24 कैरेट - ₹1,24,410/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,14,040/10 ग्राम
- चेन्नई: 24 कैरेट - ₹1,24,360/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,13,990/10 ग्राम
- कोलकाता: 24 कैरेट - ₹1,24,360/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,13,990/10 ग्राम
- हैदराबाद: 24 कैरेट - ₹1,24,360/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,13,990/10 ग्राम
- जयपुर: 24 कैरेट - ₹1,24,510/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,14,140/10 ग्राम
- भोपाल: 24 कैरेट - ₹1,24,410/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,14,040/10 ग्राम
- लखनऊ: 24 कैरेट - ₹1,24,510/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,14,140/10 ग्राम
- चंडीगढ़: 24 कैरेट - ₹1,24,510/10 ग्राम - 22 कैरेट - ₹1,14,140/10 ग्राम

सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। देशभर में चांदी का भाव घटकर ₹1,54,900 प्रति किलोग्राम पर आ गया है। लंदन के बाजारों में पहले चांदी की कमी से ग्लोबल लिक्विडिटी पर असर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है।

भारत में सोने-चांदी के दाम कैसे तय होते हैं?

भारत में सोने और चांदी की कीमतें इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रेट के आधार पर तय होती हैं। डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, आयात शुल्क डिमांड-सप्लाई और ग्लोबल इकॉनॉमिक कंडीशन का सीधा असर इन धातुओं की कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा, स्थानीय टैक्स और ज्वैलर्स के मार्जिन के हिसाब से हर शहर में रेट थोड़ा अलग होता है।

धान बिक्री के लिए किसानों में दिख रहा उत्साह, अब तक एक लाख से अधिक ने कराया पंजीकरण

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों का किसानों पर सकारात्मक असर दिख रहा है। धान की कटाई से पहले ही किसानों का उत्साह देखने योग्य है। किसी धान बिक्री के लिए अभी से पंजीकरण करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए पंजीकरण करा लिया है। जानकारी के मुताबिक, 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अब तक 1,54,035 किसानों ने अपना बिक्री पंजीकरण करा लिया है। जिसमें बाजरा के लिए 15248, ज्वार के लिए 2706 व मक्का के लिए 1509 किसानों अपना पंजीकरण करा लिया है। सत्र 2025-26 में 44127.91 मीट्रिक टन हुई धान खरीद, 2024-25 में इस अवधि तक 25329.75 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। 2369 रुपये धान कॉमन तथा 2389 रुपये (ग्रेड-ए) प्रति कुंतल से

खरीद हो रही है। अभी सिर्फ पश्चिम यूपी में धान खरीद हो रही है। पूर्वी उप्र में पहली नवंबर से खरीद होगी।

आदित्यनाथ के निर्देश पर 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान किया जा रहा है। धान बिक्री करने वाले किसानों को इस वर्ष अब तक 86.68 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस अवधि में पिछले वर्ष 43.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं बाजरा के किसानों को 8.43 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं, पिछले वर्ष इस अवधि तक यह आंकड़ा 7.63 करोड़ रुपये का था। सीएम योगी की नीतियों के कारण किसानों के हित में प्रतिवर्ष सकारात्मक पहल बढ़ती जा रही है।

किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी।

ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को ग्राम प्रधान ने गिनवाया

पहला/सीतापुर

(जीएनएस)।

विकास खण्ड पहला की ग्राम पंचायत घैला में ग्राम प्रधान रंजना सिंह चौहान के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी आरती गौड़ रोजगार सेवक रत्नेश कुमार के साथ मिलकर लगातार किए जा रहे विकास कार्य ।

ग्राम प्रधान रंजना सिंह चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण, अन्नपूर्णा उचित दर की दुकान, घैला,अकबरपुर,रहिका में तीन आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, उच्च प्राथमिक विद्यालय घैला की बाउंड्री वाल का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर की बाउंड्री वाल का निर्माण, डॉक्टर उमेश सिंह के घर से उत्तर पुलिया तक इंटरलॉकिंग का निर्माण, मनरेगा योजना से पांच

नालियों का निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, वृक्षारोपण , आर आर सी सेंटर का निर्माण,कार्य कराया गया साथ ही कई विकास कार्य प्रगति पर है जो कि बहुत ही जल्द पूरे कर लिए जाएंगे

रोजगार सेवक रत्नेश कुमार ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए गए हैं जिससे कि गांव के श्रमिकों को गांव में ही रोजगार प्राप्त हुआ

वही ग्राम प्रधान रंजना सिंह चौहान ने बताया कि काफी प्रयासों के बाद कंपोजिट विद्यालय का चयन पीएम श्री योजना के अंतर्गत किया गया और स्मार्ट क्लास चलाने के लिए कंप्यूटर कक्ष का भी निर्माण कराया जा रहा है।

जिससे कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी की शिक्षा प्राप्त होगी

मानपुर मरौरी में दर्दनाक घटना: 14 साल की सुनीता ने फांसी लगाई, बच्चों के झगड़े से आहत होकर लिया कदम

(जीएनएस)।

पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मानपुर मरौरी में शनिवार को एक 14 वर्षीय किशोरी सुनीता (टीकाराम लोधी की बेटी) ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामूली बच्चों के झगड़े से दुखी होकर उसने यह कदम उठाया।

सुनीता शनिवार सुबह घर के बाहर अन्य बच्चों संग खेल रही थी। खेलते हुए कहासुनी हो गई, जिससे वह घर में चली गई। तभी कमरे में छत के कुंडे से दुपट्टा बांध लिया। जब माता-पिता खेत से लौटे, तो शव फंदे पर लटका मिला। चीख-पुकार पर ग्रामीण जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी।

कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला ने शव उतारकर पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी है, परिजनों से पूछताछ कर रही। सुनीता शांत स्वभाव की थी, गांव में शोक की लहर

अभिन्न मानवता की मिसाल बनी 'बृज की रसोई', आशीर्वाद संग संवेदना का बांटा प्रसाद

भोजन वितरण नहीं, मानवता का प्रसाद संस्थापक विपिन शर्मा ने कहा भूखे के चेहरे पर मुस्कान ही सच्ची आराधना है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में 26 अक्टूबर 2025 इण्डियन हेल्पलाइन सोसाइटी (रजि.) द्वारा संचालित बृज की रसोई के तत्वावधान में आज रविवार को आशियाना क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर निःशुल्क भोजन वितरण सेवा का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक विपिन शर्मा ने बताया प्रेरणास्रोत बाबा नीम करौली जी की असीम कृपा से सम्पन्न इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एकत्र हुए और अकिंचन, निराश्रित बच्चों एवं असहाय, वृद्धजनों को ससम्मान पौष्टिक भोजन वितरित किया गया। श्री शर्मा ने कहा भोजन वितरण केवल अन्न दान नहीं, बल्कि मानवता का प्रसाद है। जब किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तो वही सच्ची आराधना है।

दीपक भुटियानी ने बताया कि बृज की रसोई का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि समाज में संवेदना और सह-अस्तित्व की भावना को जागृत करना है। संजय श्रीवास्तव ने कहा इस अवसर पर उपस्थित स्वयंसेवकों ने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद कर उन्हें प्रेरणादायक संदेश भी दिए अनुराग दुबे ने बताया भोजन वितरण कार्यक्रम में अनेक सामाजिक कार्यकताओं, स्थानीय निवासियों तथा युवाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सभी ने मिलकर एक सामूहिक भावना के साथ इस सेवा को सफल बनाया। वातावरण में न केवल संतोष का भाव था, बल्कि एक-दूसरे के प्रति करुणा और अपनत्व का भी सुंदर संदेश प्रसारित हुआ। विशाल माथुर ने कहा संस्था ने आमजन से अपील की कि वे भी इस सेवा यात्रा में सहभागी बनें और भूखमुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें। मुकेश कनौजिया ने बताया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी, स्थानीय नागरिक एवं युवा स्वयंसेवक शामिल हुए। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि भूख मिटाने का यह अभियान केवल त्यौहारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निरंतर सेवा यात्रा के रूप में चलता रहेगा। दिव्यांश शर्मा ने बताया कि बृज की रसोई के माध्यम से प्रत्येक रविवार सैकड़ों जरूरतमंदों तक निःशुल्क भोजन पहुँचाया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने प्रेमपूर्वक छोला आलू की सब्जी, चावल का वितरित किया। लगभग 1400 जरूरतमंदों ने इस सेवा का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में संजय श्रीवास्तव, विशाल माथुर, दीपक भुटियानी, अनुराग दुबे, मुकेश कनौजिया, दिव्यांश शर्मा, दिनेश पाण्डेय, नवल सिंह सहित अनेक समाजसेवियों ने सक्रिय योगदान दिया।

मोंथा इन राज्यों में मचा सकता है तबाही, भारी बारिश के साथ 110 किमी. की स्पीड से चलेगी हवाएं

(जीएनएस)।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव का क्षेत्र रविवार को एक गहरे दबाव में बदल गया, जो 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदलने की राह पर है। यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे कर भारी तबाही मचा सकता है। इस दौरान हवा की गति 90-110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे और झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

आईएमडी ने बताया कि यह 28 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है, जिसके बाद उसी रात यह तट से टकराएगा। तूफान के तेज होने के साथ, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी के लिए अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

आंध्र प्रदेश के इन जिलों में रेड अलर्ट

आईएमडी के वैज्ञानिक एस. जगन्नाथ कुमार ने बताया कि काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम

और नेल्लोर सहित आंध्र प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि तट पर खगोलीय ज्वार से लगभग एक मीटर ऊपर तूफान की लहरें उठने की उम्मीद है।

तीन दिन होगी भारी बारिश

ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर के बीच बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। वहीं, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, जैसे कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हुगली और बांकुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जो 28 अक्टूबर से और तेज हो जाएगी।

मछुआरों को समुद्र तट पर ना जाने की दी गई सलाह

सभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है और गंभीर स्थितियों के लिए अतिरिक्त टीमें तैनाती के लिए तैयार हैं। आईएमडी ने मछुआरों को 26 से 29 अक्टूबर तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी (यानम) और ओडिशा के तटों पर समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

सीएम ने की मीटिंग, अधिकारियों को किया अलर्ट

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को चक्रवात के बारे में अलर्ट किया और उनके साथ टेलीकांफ्रेंस की। नायडू ने कहा कि चक्रवात का प्रभाव श्रीकाकुलम से तिरुपति तक फैल सकता है और राज्य में 100 मिमी तक भारी बारिश हो सकती है, जिसके साथ 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

ओडिशा के 30 जिलों में हाई अलर्ट

ओडिशा में, सरकार ने सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा है, जिसमें मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने पीटीआई को बताया कि जिला कलेक्टरों को निचले और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से निवासियों को निकालने और बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।

हाई अलर्ट पर तमिलनाडु

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने राहत के लिए 24,149 अधिकारियों को तैनात किया है, 1,400 से अधिक मोटर पंप और 103 नावें तैयार रखी हैं, और बाढ़ की आशंका को देखते हुए 215 से अधिक राहत शिविर और 106 सामुदायिक रसोई खोली हैं। मछुआरों को कम से कम 28 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की कड़ी सलाह दी गई है, और जो पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत लौटने का आग्रह किया गया है।

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर खौफनाक हादसा: बाइक से टकराई बस में लगी भीषण आग, 20 की मौत, कई झुलसे

(जीएनएस)।

आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में शुक्रवार (24 अक्टूबर) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। हादसा इतना भयावह था कि चंद मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई। अब तक 20 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

यह हादसा तड़के करीब 3:30 बजे हुआ, जब कावेरी ट्रैवल्स की एक बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। बस में लगभग 44 यात्री सवार थे। रास्ते में बस ने कर्नूल शहर की बाहरी सीमा के पास ठल्ल-44 पर एक बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, "बाइक बस के नीचे फंस गया और उसने फ्यूल टैंक को टक्कर मार दी, जिससे जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में आग पूरी बस में फैल गई।"

स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया, वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आंखों-देखे गवाहों के मुताबिक उन्होंने बस से मदद की चीखें सुनीं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही देर

में पूरी बस जलकर राख हो गई।

हादसे के समय बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। अचानक आग लगने के बाद कुछ यात्री जाग गए और खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदने में सफल रहे, लेकिन कई लोग लपटों में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।

पूरी बस जलकर खाक, सड़क पर लगा लंबा जाम

दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि बस का ढांचा तक पहचानना मुश्किल हो गया। आग लगने के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायलों को तुरंत कर्नूल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की वजह जानने के लिए पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि बस में कुल कितने यात्री सवार थे और सुरक्षा मानकों में क्या चूक हुई।

मुख्यमंत्री नायडू और जगनमोहन रेड्डी ने जताया दुख

हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "कर्नूल जिले के चिन्गाटेकुर गांव के पास हुई इस दर्दनाक बस दुर्घटना की खबर से मैं बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। सरकार पीड़ितों और घायलों को हर संभव सहायता देगी।"

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भी हादसे पर शोक जताया। उन्होंने कहा, "यह घटना बेहद दिल दहला देने वाली है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि घायलों और प्रभावित परिवारों को तुरंत चिकित्सा और आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए।"

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं भयावह तस्वीरें

घटना के कुछ ही देर बाद बस में लगी आग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए, जिन्हें देखकर लोगों में दहशत और दुख का माहौल है। इस भीषण हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि लंबी दूरी की निजी बसों में सुरक्षा इंतजाम आखिर कितने पुख्ता हैं।

तेजस्वी यादव चुनावी रैली में बोले- हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेता वोटरों को साधने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। रैलियों और चुनावी जनसभा में विपक्षी नेता नीतीश सरकार और एनडीए पर हमला कर रहे हैं और हर दिन नए वादे कर रहे हैं। रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है।

तेजस्वी यादव ने रविवार को एक चुनावी सभा में घोषणा की कि यदि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो केंद्र सरकार द्वारा पारित 'वक्फ (संशोधन) कानून' को रद्द कर उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे।

दरअसल, कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ये दावा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा।

'भाजपा को 'भारत जलाओ पार्टी'...'

आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा, "मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ रहे हैं। उन्हीं की वजह से आरएसएस और उसके संगठन नफरत फैला रहे हैं। भाजपा को 'भारत जलाओ पार्टी' कहा जाना चाहिए।"

तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में कहा, "यह चुनाव संविधान, लोकतंत्र और भाईचारे की रक्षा की लड़ाई है। लोग 20 साल से नीतीश कुमार से परेशान हैं। सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।" उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लंबी सत्ता के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है।

एमएलसी कारी सोहैब ने दिया था विवादित बयान

इस बयान से पहले, आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सोहैब ने भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सभी बिल, वक्फ बिल समेत, फाड़कर फेंक दिए जाएंगे। इसके बाद भाजपा ने सवाल उठाया था कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र के कानून को कैसे रद्द कर सकता है।

मोदी सरकार ने पारित किया वक्फ (संशोधन) कानून

ध्यान देने वाली बात ये है कि अप्रैल 2025 में संसद ने वक्फ (संशोधन) कानून, 2024 पारित किया था। एनडीए सरकार ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला पारदर्शी कानून बताया था। वहीं, विपक्ष का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन करता है।

सीमांचल के लिए तेजस्वी यादव ने किया ये दावा

तेजस्वी यादव ने कहा "सीमांचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, अब इनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है।"

सीमांचल के विकास का वादा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा।

एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सेंटर स्थापित किया जाएगा।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि एनडीए सरकार उनके वादों की नकल कर रही है। उन्होंने कहा, "हमने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात की थी, तो नीतीश सरकार ने उसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया। हमारी सरकार बनी तो इसे 2,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।"